



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या—cm-168
03/04/2017

मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की

पटना, 03 अप्रैल 2017 :- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री आवास स्थित विमर्श सभाकक्ष में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों की गहन समीक्षा हुयी। पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री पंकज कुमार ने विभाग के कार्यों को रखा।

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि खाद्यान्न के उठाव से लेकर वितरण तक सभी चरणों पर गहन अनुश्रवण की आवश्यकता है। लोड सेल को शत-प्रतिशत करने का निर्देश विभाग को दिया गया। उठाव से लेकर पी0डी0एस0 तक पहुँचने में प्रयुक्त जी0पी0एस0 को और अधिक दुरुस्त करने की जरूरत है। मिनट टू मिनट वाहन के परिचालन का सूक्ष्मता से अनुश्रवण करने का निर्देश दिया। विभाग में केन्द्रीकृत स्तर पर संचालित नियंत्रण कक्ष तीन पालियों में 24x7 कार्यरत रहनी चाहिये। इस व्यवस्था को और भी पारदर्शी बनाने के लिये टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाय। ऐसे सॉफ्टवेयर का भी विकास करें, जिससे जी0पी0एस0 पर और भी अच्छे ढंग से निगरानी रखी जा सके। प्रखण्डों में बने आर0टी0पी0एस0 काउंटर्स पर राशन कार्ड के लिये आवेदन लिये जायें। तीस दिनों के अंदर जॉचोपरांत उसी काउंटर से आवेदनकर्ता को राशन कार्ड उपलब्ध कराये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नया राशन कार्ड बनने पर पुराना नाम काटना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित किया जाय कि नये नाम आने पर या नाम बदले जाने पर पुराने नाम का डिलिशन टेक्नोलॉजी प्रभावी ढंग से काम करे। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का सामाजिक अंकेक्षण कराने के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने मनरेगा की भांति अंकेक्षण कमिटी बनाकर सामाजिक अंकेक्षण की बात कही। एस0ई0सी0सी0 के आधार पर तैयार कुल लाभुकों का 68 प्रतिशत ही आधार से लिंकअप है, जिसे शत-प्रतिशत लाभुकों को आधार से सिडिंग करने निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधार सिडिंग होने से वितरण में पारदर्शिता और दुहराव से बचा जा सकेगा। राशन कार्ड बनाना एक सतत् कार्य है, जो हमेशा चलते रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एफ0सी0आई0 और रेलवे के दैनिक उठाव प्रक्रिया पर नजर रखनी होगी ताकि समय पर नियमित रूप से लाभुकों को अनाज मिल सके।

बैठक में मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री मदन सहनी, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त श्री शिशिर कुमार सिन्हा, प्रधान सचिव वित्त श्री रवि मितल, प्रधान सचिव मंत्रिमण्डल समन्वय श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चन्द्रा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री पंकज कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह उपस्थित थे।
